(c) what is the cost of each horse and what has been the extent of loss due to the death and illness of these horses; and

(d) what steps Government have taken or propose to take to save the lives of such highly pedigreed race horses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) This Department take appropriate control measure according to the disease status in the State|Country.

Lower amount of subsidy to farmers to India

7141. CHAUDHARY HARMOHAN SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the subsidy being provided in the country for agricultural production is low in comparison to that given in the foreign countries;

(b) if so what are the details of the amounts of subsidy being given by different countries of the World; and

(c) what efforts are being made by Government to provide subsidy to boost agricultural production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) The estimates of Producers Subsidy Equivalent (net of input subsidies and output taxes) as percentage of value of agricultural production as worked out by Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) for 1990 are as under:

Country	Producer subsidy equivalent as percentage value of agricultural production
Japan	68
EC	48
USA	30
Canada	41
Australia	11

(c) The Government policy aims at reducing the level of subsidy in the economy including agriculture with a view to reducing fiscal imbalances so that development activities are financed in a non-inflationary manner. A number of incentives are being provided under various crop specific development prorammes to boost agricultural production.

अंगोरा ऊन

7142. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पिछड़े प्रदेश में किसान अंगोरा किस्म के खरगोश

पालकर, उनको ऊन बचकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रह हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय अंगोरा किस्म की ऊन की कीमत 750 रुपये से 800 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है और इस वष बजट में वस्त्रों पर उत्पादकर लगा देने से अंगोरा ऊन के बाजार को एक गहरा धक्का लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अंगोरा ऊन के लघु उद्योग को चौपट होने से चाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि अंगोरा ऊन की कीमत 750/– रुपए से लेकर 800/– रु. प्रति कि. ग्रा. तक होती है । इस वष के बजट में वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप अंगोरा ऊन के बाजार को कोई गहरा धक्का नहीं पहुंचा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Oil seed production

7143. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have proposed any scheme in regard to oilseed production;

(b) if so, whether any arrangements are being considered to provide seeds to farmers on concessional and timely basis;

(c) whether there is also a provision made in the above scheme for exchange of seeds between different states;

(d) if so, whether this scheme has been introduced in Madhya Pradesh; and

(e) what are the concrete proposals formulated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SRH S. KRISHNA KUMAR): (a) to (e) A Centrally Sponsored Oil Seed Production Programme is in operation in 21 States including Madhya Pradesh to increase the production and productivity of oilseed crops. This scheme has a component on assistance for seed production and distribution. There is no component of seed exchange under the Oil Seed Produnotion Programme.

पौध-संरक्षण हेतु सहायता

7144. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौध-संरक्षण यंत्रों, कीटनाशी, कृमिनाशक तथा खरपतवार नाशक औषधियों पर दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को इस वित्तीय वर्ष से बंद कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली में हुई सभी राज्यों के सचिवों तथा अन्य प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय संगोष्ठी में उक्त केन्द्रीय सहायता को जारी रखने का अनुरोध किया गया था ;

(ग) क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान होगा; यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या-क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार किसानों के हित में चल रही इस प्रकार की योजनाओं को पुनः आरम्भ करने पर विचार करेगी ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?